भारतीय जनता पार्टी

गुजरात विधानसभा चुनाव 2012

Sankalp Patra

संक्षेप में

प्रस्तावना

- कुशल और पारदर्शी प्रशासन के साथ ग्यारह वर्षों में 4,000 दिन की ऐतिहासिक विकास यात्रा
- गुजरात प्रशासन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना –250 से ज्यादा पुरस्कार हासिल किये, प्रत्येक पन्द्रह दिन पर औसतन एक पुरस्कार।
- तेजी से फिर भी संतुलित आर्थिक विकास– सभी तीन क्षेत्रों–उद्योग, कृषि और सेवाओं में 10 वर्षों में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा विकास
- समग्र, व्यापक और चौतरफा विकास
- गुजरात ने वैश्विक ऊंचाइयों को छुआ और विश्व स्तर पर कीर्तीमान स्थापित किये
- पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति आय चार गुना बढी–2001 में 19,823 से बढ़कर 2011 में 75,115
- गुजरात के पहले 42 वर्ष (1960 से 2002) में योजनागत खर्च 55,534 रुपये था। जबकि इसके विपरीत पिछले दस वर्ष में गुजरात के विकास के लिए योजनागत खर्च 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- हमने गुजरात में करों में वृद्धि किये बिना गुजरात के राजस्व घाटे की कायापलट कर उसे राजस्व अधिशेष राज्य बना दिया।
- निरंतर विकास और इसके लिए हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अनुरुप और स्थिर शासन

गुजरात के लिए आर्थिक विकास कोई नया तथ्य नहीं है। अब चुनौती है प्रगति की रफ्तार को बनाए रखना और विकास की नई ऊंचाइयों को छूना। हमारी काफी उपलब्धियां रहीं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। हम और अधिक प्रयास कर रहे हैं। हमारा सपना है:

- दुनिया के विकसित देशों के बराबर समग्र विकास
- और अधिक आधुनिक और पारदर्शी प्रशासन
- सभी के लिए सार्वजनिक भागीदारी और अवसर

भाजपा का संकल्प

शिक्षा

- प्राइमरी स्कूलों में शत–प्रतिशत दाखिले का लक्ष्य हासिल और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने का अनुपात घटकर 2 प्रतिशत। हम बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर को शून्य पर ले आएंगे और उसे गुणोत्सव जैसी पहल के जरिये उसी स्तर पर स्थिर कर देंगे, हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार करेंगे।
- गुजरात एक ज्ञानवान समाज की ओर अग्रसर है जहां माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार हो रहा है।
- **गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना**
- **शहरी इलाकों में छात्रावासों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा ताकि 40,000 छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था की जा सके। लड़कियों के छात्रावास पर मुख्य रुप से ध्यान दिया जाएगा।**
- खेल स्कूल और ग्रीन स्कूल जैसे नये तरह के स्कूल, विशेष तरह के अधिक विश्वविद्यालय और ग्लोबल संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- विशेष तरह के विश्वविद्यालयों की स्थापना की परम्परा को जारी रखते हुए, हम समुद्री, ऑटो, बुनियादी ढांचे, इंजीनियरिग, प्रबंधन, बायो टेक्नॉलॉजी आदि के लिए ऐसे और संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
- विद्यालक्ष्मी बांड का दायरा बढ़ाकर इसमें **राज्य भर के सरकारी स्कूलों** की सभी लड़कियों को शामिल किया जाएगा (अभी यह सुविधा केवल उन गांवों में थी जहां महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है)
- गुणवत्ता के आधार पर शहरी शिक्षा समितियों को 100 प्रतिशत वेतन अनुदान
- विभिन्न जिलों में नये दिवा विद्यालय
- आदिवासी इलाकों, रेत से घिरे क्षेत्रों और नमक बनाने वाले इलाकों में सहायता अनुदान स्कूलों की स्थापना को प्राथमिकता
- विदेशी भाषाएं जैसे चीनी, जापानी पढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्वास्थ्य

- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, संस्थानों और सुविधाओं का विकेन्द्रीकरण
- **आदिवासी क्षेत्रों सहित प्रत्येक प्रमुख जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी**
- **सरकारी स्व वित्त मेडिकल कॉलेजों के जरुरतमंद छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरु की जाएगी।**
- हाल ही में स्थापित गुजरात मेडिकल सेवा निगम के जरिये बहुत ही कम कीमत पर **जेनेरिक दवाएं**

और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

- **मुख्यमंत्री अमृतम (एमए) योजना** का धीरे–धीरे विस्तार किया जाएगा ताकि इसमें नव (निचले) मध्यम वर्ग के परिवारों को शामिल किया जा सके। इस समय गरीब परिवारों को जानलेवा बीमारियों जैसे कैंसर, दिल की बीमारियों, स्नायु रोगों तथा किडनी की बीमारी के इलाज के लिए प्रति वर्ष 2,00,000 रुपये देने की व्यवस्था है।
- सूरत, वडौदरा, राजकोट और उत्तरी गुजरात में कैंसर, किडनी और दिल की बीमारियों के इलाज के लिए नये **स्पेशलिटी अस्पताल** बनाए जाएंगे।
- मां और बच्चे की देखभाल के लिए विभिन्न पहल की जाएंगी जिनमें कुपोषण से निपटने के लिए **मिशन बलम सुखम,** नवजात शिशु और मां को सुरक्षित ले जाने के लिए **खिलखिलात वैन**, **नंद घर** (आधुनिक आंगनवाड़ियां), **माता यशोदा पुरस्कार** शामिल हैं।
- **वरिष्ठ नागरिकों** के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल के अंतर्गत बुजुर्गों के लिए अस्पताल/वार्ड, एमडी (बुजुर्गों कोर्स की शुरुआत और रविवार को ओपीडी क्लीनिक की व्यवस्था शामिल है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर ओल्ड ऐज होम को बढ़ावा देने के लिए चिरायु योजना।
- स्वास्थ्य सेवाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा और जिला सिविल अस्पतालों में दिल की बीमारियों के इलाज के लिए इन्टेनसिव केयर यूनिट, किडनी डायलेसिस केन्द्र और नवजात शिशु के लिए इंटेनसिव केयर यूनिट की व्यवस्था होगी।.

कृषि और पशु पालन

- राज्य में पिछले 40 वर्षों में केवल 6.70 लाख विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गए, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने केवल 11 वर्षों में ऐसे 4 लाख कनेक्शन प्रदान किये, हम आगे ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे सभी लंबित मांगों को तत्काल पूरा किया जा सके।
- हमारे बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसे काम में लाने के निरंतर अभियान के कारण अपने किसानों को 57 अंधेरे वाले क्षेत्रों से मुक्त किया जिसे वह पिछले कई वर्षों से भुगत रहे थे। हम बारिश के पानी को इकट्ठा करने और बचत अभियान जारी रखेंगे ताकि हमारे किसानों को फिर से अंधेरे का सामना नहीं करना पड़े।
- किसानों और सखी मंडलों को कृषि और व्यावसायिक कर्ज में सहायता और छूट
- खेती में मशीनों के इस्तेमाल और कृषि के आधुनिकीकरण से कृषि उत्पादन और बढ़ाया जाएगा।
- हम सात लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बूंद–बूंद करके (ड्रिप)/फव्वारे से सिंचाई की व्यवस्था कर चुके हैं। हम इन प्रणालियों के अंतर्गत और अधिक जमीन को लाएंगे और अपने आदर्श वाक्य 'प्रति बूंद अधिक फसल' को और आगे बढ़ाएंगे।
- कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

- पशुओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड दिये जाएंगे
- वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की तरह प्रत्येक दो वर्ष में ग्लोबल एग्रीटेक मेला आयोजित किया जाएगा।
- राज्य सरकार कपास उगाने वाले किसानों से लिये जाने वाले बीमा के अधिक प्रीमियम का बोझ बांटेगी
- पिछले दशक में सब्जियों और फलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। हमारी सब्जियां और फल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचे। ग्रीन हाउस, पौली हाउस, नेट हाउस आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि गुजरात देश की **सब्जी की डलिया** बन सके।
- छोटे और सीमांत किसान सहकारी संगठनों से लिये गए कृषि ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज देते हैं। **सरकार 3 प्रतिशत ब्याज देकर उनका बोझ कम करेगी ताकि किसानों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़े।**
- पूर्व में कांग्रेस ने काफी गोचर भूमि उद्योगों को दे दी। पिछले 11 वर्षों में उद्योगों को आबंटित की गई कुल भूमि में से **सिर्फ 4.97 प्रतिशत गोचर भूमि थी।** इसके अलावा वर्तमान राज्य सरकार की प्रगतिशील नीतियों के कारण, पिछले दशक में गोचर भूमि 6800 हेक्टेयर बढ़ी है। सरकार ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर गोचर भूमि के गुणात्मक सुधार के लिए हर संभव प्रयास किये हैं। इस दिशा में बढ़ते हुए सरकार मवेशियों की आबादी और उन्हें पालने वाले परिवारों की भलाई के लिए काम करना जारी रखेगी।
- **नवगठित गोचर विकास बोर्ड के जरिये गोचर विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा**
- प्रत्येक जिले में कोल्ड स्टोरेज और एग्री–प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी

सिंचाई

- 16 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई जाएगी
- कृषि के अंतर्गत विस्तार क्षेत्र पर विशेष ध्यान
- उत्तरी गुजरात के तालाबों को बारिश के पानी से भरने का भारी भरकम कार्य किया जाएगा
- 'सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई (एसएयूएनआई) योजना के अंतर्गत अगले तीन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये की लागत से सौराष्ट्र के सभी बांधों को नर्मदा के पानी से भरा जाएगा
- पोरबंदर जिले के रणवाव और कुटियाना तथा जूनागढ़ जिले के मंगरौल और कैशोड के अलावा भाल के घेड़ इलाके में नहर का निर्माण किया जाएगा ताकि बारिश का पानी समुद्र में जाने से रोका जा सके और उसे काम में लाया जा सके, भू–क्षरण पर अंकुश लगाया जाएगा और हजारों हेक्टेयर भूमि पुनर्निर्मित की जाएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद से, कलपसार परियोजना तेजी से कार्यान्वित की जाएगी

- नर्मदा नदी पर भड़भूत बराज का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

समग्र विकास

- पिछले एक वर्ष में बहुत बड़े परिवर्तनों के कारण गुजरात में मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या बढ़ी है। इस नव मध्यम वर्ग की श्रेणी को परिभाषित किया जाएगा और इस श्रेणी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी। इसी तरह आमदनी और अन्य मानदंडों पर आधारित, मध्यम वर्ग को परिभाषित किया जाएगा ताकि उनके लिए कल्याण योजनाएं शुरु की जा सकें।
- ' मेरा इलाका मेरा अपना घर हो' ये हर व्यक्ति का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए हम मुख्यमंत्रीश्री गृह समृद्धि योजना लागू करेंगे।
- **मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक अलग विभाग की स्थापना कर 33,000 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना लागू की जाएगी।**
- पारदर्शी और समयबद्ध आबंटन सुनिश्चित करने के लिए, **राज्य स्तर पर एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी**
- परियोजना को लोगों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जाएगा और जीडीसीआर, एफएसआई और जमीन की कीमतों में रियायत दी जाएगी।
- अगले पांच वर्षों में कुल **50 लाख पक्के मकान** बनाए जाएंगे जिनमें **ग्रामीण इलाकों में 28 लाख मकान और शहरी इलाकों में 22 लाख मकान** बनाना शामिल है।
- शहरी इलाकों में **झोपड़पट्टियों में रहने वाले 7.5 लाख लोगों** में से प्रत्येक को बुनियादी सुख–सुविधाओं के साथ **36 वर्ग मीटर पर बने मकान** दिये जाएंगे।
- एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले **शहरी निम्न मध्यम वर्गीय लोगों** से केवल 50,000 रुपये लेकर **उनके लिए 2 कमरों और रसोईघर के साथ 7.5 लाख मकान बनाए जाएंगे।**
- एक लाख रुपये से ढाई लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले **शहरी निम्न मध्यम वर्ग के लिए सस्ते शहरी आवास के अंतर्गत 3.5 लाख मकानों का निर्माण कराया जाएगा।**
- शहरी इलाकों में ढाई लाख रुपये से अधिक लेकिन पांच लाख रुपये से कम की वार्षिक आय वाले **मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 2बैडरुम हॉल किचन वाले 3.5 लाख मकान बनाए जाएंगे।**
- औद्योगिक श्रमिकों, श्रमिकों, कुशल श्रमिकों आदि को उनके काम करने के स्थान के नजदीक सस्ती दर पर आवास सुविधा प्रदान करने के लिए हाउसिंग टाउनशिप योजना।

पूर्व की सरकारें 40 वर्षों में लोगों को केवल 12 लाख (शहरी और ग्रामीण दोनों को मिलाकर) मकान दे पाईं यानि प्रति वर्ष औसतन 30,000 मकान जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने पिछले 11 वर्ष में प्रति वर्ष औसतन 1 लाख मकान की दर से 22 लाख मकान दिये। जिन लोगों का पिछला रिकॉर्ड एक वर्ष

में केवल 30,000 मकान बनाने का रहा है, वे आज वादा कर रहे हैं कि प्रति वर्ष 3 लाख मकान बनाएंगे। अगर उन्होंने 40 वर्षों में यह काम किया होता तो आज कोई भी बेघर नहीं होता।

- **दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता होने पर सभी नागरिकों को बीमा सुविधा दी जाएगी।**
- **सामूहिक विवाह के लिए सहायता दी जाएगी चाहे वह किसी भी जाति के हों या उनका आय का कुछ भी स्तर हो।**
- शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सार्वजनिक सेवाओं को अधिक प्रभावकारी और व्यापक बनाया जाएगा ताकि मध्यम वर्ग उस पर निर्भर कर सके और उसे निजी सेवाओं के लिए उसे बहुत अधिक पैसा देने की जरुरत न पड़े। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में काफी कार्य किया है। हमने अनेक उदाहरण कायम किये हैं जैसे 108 इमरजेंसी सेवाएं, बीआरटीएस, नई एसटी बसें, सिटी सिविक सेंटर और एक दिन का शासन, चलता–फिरता आईसीयू, नये इंजीनियरिंग कॉलेज आदि। गुजरात सरकार देश में सबसे कम फीस पर इंजीनियरिंग शिक्षा देगी। सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं को बेहतर और कार्यक्षम बनाना और यहां तक कि निजी क्षेत्र से बेहतर बनाना हमारे शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे मध्यम वर्ग को सस्ती दरों पर अच्छी क्वालिटी की सेवाएं मिल सकेंगी।
- राज्य के सभी शहरी इलाकों में 4000 करोड़ रुपये की लागत से पानी की भूमिगत निकासी के चरणबद्ध और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए योजनाएं।
- हम बिना किसी बाधा के गांवों में घरों तक चौबीस घंटे बिजली पहुंचा रहे हैं। हमने हजारों परिवारों को सफलतापूर्वक पाइपलाईन के जरिये खाना पकाने की गैस उपलब्ध कराई है अगले पांच वर्षों में अनेक अन्य को प्रदान करेंगे। इसके साथ–साथ हम छत पर सौर ऊर्जा योजना की शुरुआत करेंगे जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा मिलने के साथ–साथ अतिरिक्त आमदनी का दोहरा फायदा होगा।

वंचितों का विकास

• वर्तमान सरकार ने बिचौलियों का सफलतापूर्व सफाया किया है और अब तक गरीब कल्याण मेलों के जरिये करीब 85 लाख गरीबों को 13,000 करोड् रुपये अनुग्रह वितरित किया है। हम अगले पांच वर्षों में गरीबी उन्मूलन की सभी योजनाओं को जोड़कर गरीब कल्याण मेलों को और अधिक विज्ञान आधारित बनाएंगे।

- दसवीं कक्षा के परिणाम के साथ जाति प्रमाणपत्र दिये जाएंगे ताकि माता–पिता और छात्रों को इसे लेने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े।
- अनुसूचित जातियों, अति पिछड़े वर्ग (अति पछाड़ जाति) के भूमिहीन लोगों को अपने जीवन में एक बार अधिकतम दो एकड़ जमीन खरीदने के लिए काश्तदारी अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी

जाएगी।

- वनबंधु कल्याण योजना और सागरखेडू विकास योजना की र्त पर अनुसूचित जातियों के लिए एक विकास पैक्ेज शुरु किया जाएगा।
- पिछले पांच वर्षों में हमने वनबंधु कल्याण योजना और सागरखेडू विकास योजना के जरिये पूर्वी आदिवासी क्षेत्रों और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वंचित वर्गों के सुनियोजित विकास का काम हाथ में लिया। अगले पांच वर्ष में हम पहले ही आदिवासियों के लिए 40,000 करोड़ रुपये और तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए 21,000 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी पैकेज शुरु कर चुके हैं। इन पैकेजों को सख्ती से लागू करके हम सुनिश्चित करेंगे कि इनका भी गुजरात के अन्य विकसित इलाकों के समान विकास हो।
- हम आदिवासी इलाकों में उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन देंगे जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- हम ओबीसी की 'क्रीमी लेयर' के लिए सीमा में संशोधन कर उसे प्रति वर्ष 6 लाख रुपये कर देंगे।
- पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए विशेष छात्रावास सुविधा
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण इलाकों में रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना पक्का मकान मिले जिसमें बुनियादी सुविधाएं हों ताकि उन्हें कच्चे मकान में रहकर आने वाली कठिनाइयों से राहत मिल सके।

रोजगार

- औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास के साथ 30 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित।
- इसके अलावा 30 लाख से ज्यादा को मिशन मंगलम योजना के अंतर्गत स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।
- रोजगार से जुड़े लाभों और अवसरों के लिए युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- युवकों में ठोस कौशल और औद्योगिक उद्यमिता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे।
- कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किये जाएंगे। यह अगले 10 वर्षों में 2.5 करोड़ कुशल श्रमिक तैयार करने के लिए एक खाका और पाठ्यक्रम तैयार करेगा ताकि उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा किया जा सके।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहचान पत्र दिये जाएंगे, इस बात की भी व्यवस्था की जाएगी कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए।
- श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी।

- स्वरोजगार औश्र प्रशिक्षण के लिए आसान कर्ज सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ व्यवस्थ्ज्ञा की जाएगी। जहां जरुरी होगा, ऐसे कर्जों के लिए सरकार गारंटर होगी।
- गुजरात ऑटो हब के रुप में उभर रहा है। तदनुसार मानव संसाधन की जरुरत को पूरा करने के लिए एक नया संस्थान और पाठ्यक्रम शुरु किया जाएगा।

वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- गुजरात की पहचान 'हरित' राज्य के रुप में बनाने के लिए प्रतिबद्ध
- वन क्षेत्रों में घास वाली भूमि पर चारा उगाने का विशेष कार्यक्रम
- गुजरात के गांवों और उनके आसपास मौजूद झीलों को प्रदूषित होने से रोकने और उनके विकास के लिए एक झील विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अध्ययन और कार्य योजना
- देश के कुल सीईआर में गुजरात का हिस्सा 17.28 प्रतिशत है। हमारी सरकार इस स्थिति को बनाए रखने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी और प्रौद्योगिकी विकास को गति प्रदान करेगी जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। हम इस संबंध में जन जागरुकता फैलाने के लिए तीव्र अभियान चलाएंगे।
- आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण रोकना हमारा लक्ष्य
- गांधीनगर को सौर शहर और कार्बन न्यूट्रल शहर के रुप में विकसित करने पर विशेष ध्यान

महिला और बाल विकास

- बालिका के जन्म के प्रति परिवारों में सकारात्मक रवैये को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति बनाई जाएगी
- सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को शामिल करने के लिए विद्या लक्ष्मी बांड छात्रवृत्ति कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा
- गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए सरकारी सुविधाओं को मजबूत बनाने के अलावा चिरंजीवी योजना को अधिक प्रभावकारी बनाया जाएगा
- महिला कॉलेजों के लिए विशेष प्रावधान, महिलाओं के आईटीआई और महिला छात्रावास
- महिलाओं को महिलाओं से न्याय दिलाने के लिए अधिक तालुकों में नारी अदालतों का गठन किया जाएगा
- 24 लाख सदस्यों वाले 2.5 लाख सखी मंडलों के लिए कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ''मिशन मंगलम'' के अंतर्गत महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। ऐसे कर्जों पर हम ब्याज सब्सिडी देंगे।

युवा

- युवाओं के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए एक नई युवा नीति बनाई जाएगी। इसमें खेल–कूद, रोजगार और रोजगार क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- राज्य में 2010 से एक महीने का खेल महाकुंभ हो रहा है। इसे अधिक परिणामोन्मुख बनाया जाएगा।
- जिलों में खेल स्कूल खोलकर, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा और तैयार किया जाएगा जो खेलों को भी अपना करियर बनाना चाहते हैं
- प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे समुद्री खेल, जल क्रीड़ा, पर्वतारोहण और साहसिक खेल और तीरंदाजी।
- राज्य में, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से एक नीति तैयार की जाएगी

खाद्य सुरक्षा

- सरकार की सहायता से सखी मॉडलों के जरिये गरीबों को खाद्यान्न प्रदान करने के लिए सरकार की सहायता से अन्नपूर्णा योजना
- गुजरात की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया, उसे और मजबूत बनाया जाएगा और ग्राम विश्वग्राम केन्द्रों के जरिये राशन के लिए कूपन वितरित किये जाएंगे।

राजस्व

- सम्पत्ति के अधिकार की जांच के लिए राज्य सरकार एक प्राधिकरण गठित करेगी
- कई एजेंसियों से एनए की क्लीयरेंस लेना जरुरी होगा। पिछले अनेक वर्षों से जारी व्यवस्था की तरह आवेदनकर्ता को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भागना न पड़े, इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा।
- एनए की इजाजत में तेजी लाने के लिए कुछ कलेक्टर कार्यालयों में खेले दरबार की व्यवस्था कुछ और जिलों में की जाएगी।
- किसानों के बीच स्वेच्छा/आपसी सहमति से भूमि के आदान–प्रदान के मामले में स्टैंप ड्यूटी से छूट दी जाएगी।

.

विद्युत और ऊर्जा के अन्य स्रोत

- पांच वर्ष के भीतर विद्युत उत्पादन दोगुना हो जाएगा
- प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग को विश्व स्तर तक पहुंचाया जाएगा
- सौर और पवन ऊर्जा सहित ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों में आगे
- गुजरात सौर ऊर्जा क्षेत्र में उदाहरण बन जाएगा
- घरों की छतों पर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा
- साथ ही देश के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस इस्तेमालकर्ता और वितरण नेटवर्क के मालिक के रुप में राज्य की स्थिति को बरकरार रखते हुए, लोगों को प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पेयजल

- देश के 30 प्रतिशत औसत की तुलना में राज्य में 75 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में इसमें और अधिक आबादी को शामिल किया जाएगा
- जल प्रबंधन समितियों को चिरस्थायी बनाया जाएबा

शहरी विकास

- शहरी गरीबों के लिए विशेष आवास पैकेज– गरीब 25 लाख मकान बनाए जाएंगे
- अलग–अलग शहरी शौचालयों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना
- 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो रेल सेवाएं (एमईजीए), अन्य शहरों में बीआरटीएस
- बीआरटीएस और मेट्रो जैसी आधुनिक, तेज और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सही विकास
- अन्य शहरों में नदी के सामने का विकास, कुछ और ट्विन शहर
- 2011 की जनगणना के आधार पर नये नगर निगमों का गठन
- शहरी गरीबों के लिए खासतौर पर 2007 में 13,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ शहरी गरीब समृद्धि योजना शुरु की गई। अगले पांच वर्ष में इस पैकेज को बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाएगा

बनियादी ढांचा

- 10 और 4/6 लेन वाली सड़कों की लंबाई दोहरी करना
- ग्रामीण सड़कों सहित सड़कों का विस्तार और उन्हें पक्का करना
- सड़कों, रेलवे का विश्व स्तरीय विकास

- वैश्विक मानदंडों के साथ बंदरगाहों का विकास
- अहमदाबाद, पालनपुर, वडौदरा, दहेज, हजीरा में लॉजिस्टिक पार्को विकसित करना
- अंतरराज्यीय जल परिवहन की व्यवस्था शुरु की जाएगी। इस पहल के अंतर्गत पहले रो–रो नौका परियोजना भावनगर से दहेज तक विकसित की जाएगी। इन प्रयासों का अन्य जगहों पर भी विस्तार किया जाएगा।
- हमने अहमदाबाद नगर निगम के लिए मल्टीमॉडल वहनीय परिवहन प्राधिकरण (एमएटीए) की स्थापना का फैसला किया है जिससे परिवहन के विभिन्न अत्याधुनिक प्रणालियों एसटी बस, सिटी बस, बीआरटीएस और मेट्रो रेल की मदद से एक समन्वित प्रणाली स्थापित की जा सके ताकि लंबी यात्रा के दौरान अलग–अलग वाहनों के लिए यात्रियों को अलग–अलग टिकट न लेना पड़े।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर नये विकसित औद्योगिक क्षेत्रों सहित आखिरी मील तक रेल संपर्क
- नागर विमानन उद्योग तेजी से विकसित किया जाएगा। ढोलरा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।

पर्यटन

- सपुतड़ा, पावगढ़ और जीमर जैसे पर्यटन स्थलों पर विशेष ध्यान
- पर्यटन स्थलों पर बुनियादी ढांचा तैयार करना और बजट होटल, गैस्ट हाउस आदि जैसी सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहन
- द्वारका और बैट द्वारका के बीच हावर क्राफ्ट सहित समुद्री यात्रा की व्यवस्था की जाएगी
- दांडी यात्रा मार्ग को धरोहर गलियारे के रुप में विकसित किया जाएगा
- भारत के महान संतों के जीवन और उनकी शिक्षाओं की जानकारी देने के लिए संत नगरी की स्थापना की जाएगी
- डांग्स की उन जगहों को जहां भगवान राम गए थे एक पर्यटन सर्किट ''श्रीराम पगडंडी'' के रुप में विकसित किया जाएगा
- पर्यटन और अतिथि सत्कार प्रबंध, पर्यटन गाइड, पर्यटन पुलिस और पर्यटन प्रकाशन के जरिये हम पर्यटन उद्योग में गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे
- महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए नौका सेवा
- एक समय सीमा के भीतर सरदार सरोवर परियोजना बांध स्थल पर सरदार वल्लभभाई पटेल की समृति में एकता की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होगी

सुरक्षा

- आज गुजरात की पुलिस भारत में सबसे नई है और हाल के वर्षों में पुलिस बल में बड़ी संख्या में नियुक्ति के कारण शिक्षित और टेक्नो सेवी है। पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे युवकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- गुजरात का लोक अदालत और सायंकालीन अदालतों का सफल अनुभव रहा। इसका विस्तार किया जाएगा और मजबूत बनाया जाएगा।
- महिलाओं के लिए विशेष लोक अदालतें
- निजी सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देने के बारे में विचार किया जाएगा।

बंदरगाह

- बंदरगाहों के आसपास बंदरगाह शहर विकसित किये जाएंगे
- बंदरगाह प्रबंधन के लिए समन्वित बंदरगाह प्रबंध प्रणाली लागू की जाएगी
- गुजरात के बंदरगाहों से इस समय 323 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटी प्रति वर्ष) सामान लाया–ले जाया जाता है। हम इसे बढ़ाकर 2015–16 तक 500 एमएमटी प्रति वर्ष और 2020 तक 800 एमएमटी प्रति वर्ष कर देंगे।
- गुजरात को दक्षिण एशिया के जहाज निर्माण हब के रुप में विकसित किया जाएगा
- नौवहन और बंदरगाह क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए संस्थानों की स्थापना की जाएगी और पाठ्यक्रम शुरु किये जाएंगे।
- मछुआरों के लिए विशेष जेटी स्थापित की जाएंगी
- इस समय राज्य में 2 एलएनजी टर्मिनल उपलब्ध हैं। हम ऐसे और टर्मिनल विकसित करेंगे।

ई–गवर्नेंस, आईटी और बीटी

- गुजरात में राज्यव्यापी ब्राडबैंड कनेक्टीविटी है। अब राज्य सरकार सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक केन्द्रों में राज्य भर में वाईफाई नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- ई–गवर्नेंस के जरिये हम निकटतम संभावित स्थान पर नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करेंगे।

- सोशल मीडिया चलित वृहद परामर्शदात्री नीति तैयार की जाएगी
- डिसटेंस लर्निंग और अध्यापन तथा टेलीमेडिसिन का राज्य भर में प्रसार किया जाएगा
- एक दिन के शासन केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा
- राज्य के युवक सही नौकरियां ढूंढ सकें इसके लिए एक नया पोर्टल शुरु किया जाएगा
- गुजरात उपग्रह टेक्नोलॉजी के प्रयोग में आगे रहा है। बीआईएसएजी संस्थान भारत में मशहूर है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए इस टेक्नोलॉजी का धरती की सतह पर अधिक से अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा।
- नौवहन जैव प्रौद्योगिकी खासतौर से समुद्री शैवाल संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

ग्लोबल गुजरात

- 13 विशेष निवेश क्षेत्र विकसित किये जाएंगे
- औद्योगिक क्षेत्र में आगे अतः अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाएंगे
- विश्व स्तर का आधुनिक और सुनियोजित शहर, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और स्मार्ट शहर
- मानव संसाधन के संबंध में विजन तैयार किया जाएगा और विशेष कौशल प्राप्त कामगारों सहित प्रशिक्षित तथा कुशल कामगारों की व्यवस्था की जाएगी
- गुजरात में प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च अध्ययन और अनुसंधान तक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर राज्य को एक ज्ञानवान समाज के रुप में विकास किया जाएगा
- राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग 1615 केडब्ल्यूएच है जबकि देश में बिजली का उपभोग 1615 केडब्ल्यूएच है। इसे विश्व स्तर 2782 केडब्ल्यूएच के बराबर लाया जाएगा
- गुजरात को पूरी तरह गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा
- सौर और पवन ऊर्जा सहित परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में गुजरात लीडर की भूमिका निभाएगा और उदाहरण बनेगा।
- बंदरगाह क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा। बंदरगाहों को सड़कों और रेलों से जोड़ा जाएगा।
- कृषि और बागवानी का विकास जारी रहेगा। संसाधनों का अधिक प्रभावकारी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। पीछे और आगे की कड़ी को बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा

प्रशासन

- सेवा का अधिकार कानून लागू किया जाएगा

- भविष्य की जरुरतों के बारे में सही तथ्यों के साथ सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए वार्षिक अभियान चलाया जाएगा
- नवगठित जिलों और तालुकों को क्रियाशील बनाने और एटीवीटी एप्रोच को मजबूत बनाकर प्रशासन का और विकेन्द्रीकरण
- 500 और सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा
- सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए आयु सीमा हाल ही में विभिन्न पदों के लिए 25 से बढ़ाकर 28 और 28 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। विशेष वर्गों के लिये आयु सीमा में ढील जारी रहेगी। सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी नौकरियों के बोर्ड में इसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि रोजगार के अधिक अवसर खुल सकें।

वित्तीय प्रबंधन

- अगले पांच वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये का योजना खर्च